reported by the State Government of Tamil Nadu that the Supreme Court has not given any direction against payment of piece rate wages. However, the Government of Tamil Nadu have fixed minimum rates of wages for all workers, irrespective of age, for different jobs in match industry as against the Supreme Court direction to pay atleast 60% of prescribed minimum wages for adult workers to the working children.

असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों के कानूनी अधिकार

545. **श्री ईश दत्त यादव** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि असंगठित क्षेत्र में करोड़ों श्रमिकों को उनके कानूनी अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) असंगठित क्षेत्र के ऐसे श्रमिकों को पर्याप्त कानूनी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए गत दो वर्षों के दौरान सरकार ने क्या-क्या कदम उठाये हैं ; और

(घ) इस दिशा में कितनी प्रगति हुई है ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पबन सिंह घटोवार) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) और (घ) वर्तमान कानूनी सहायता योजना के अनुसार जिन व्यक्तियों की सभी स्रोतों से आय 6000 से अधिक नहीं है वे उच्च न्यायालय स्तर तक चलाये जाने वाले मामलों के लिए कानूनी सहायता प्राप्त करने के हकदार हैं । उच्चतम न्यायालय में चलाए जा जाने वाले मामलों के लिए उन व्यक्तियों के लिए कानूनी सहायता उपलब्ध है जिनकी सभी स्रोतों से आय 9,000 रु० से अधिक नहीं है । हाल ही में समाज के अपेक्षाकृत बड़े वर्गों को कानूनी सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से इस योजना को उन सभी व्यक्तियों पर लागू किया गया है जिनकी वार्षिक आय 12,000 रु० प्रति वर्ष से अधिक नहीं है । वार्षिक आय की सीमा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, विमुक्त जातियों, खानाबदोश जनजातियों से संबंधित व्यक्तियों, महिलाओं और बालकों पर लागू नहीं होती जो निःशुल्क कानूनी सेवाओं के हकदार हैं।

पिछले दो वर्षों में 2,87,270 व्यक्ति सरकार की कानूनी सहायता योजना से लाभान्वित हुए हैं ।

Cases of industrial disputes pending in Madras region

546. SHRI S. MADHAVAN : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a large number of industrial disputes are pending in the Madras region and if so, the details thereof ; and

(b) whether the labour organisations have demanded for creation of additional courts to clear the pending cases in the Madras region and if so, the action taken thereon ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI PABAN SINGH GHATOWAR): (a) and (b) The information is being collected and will be laid on the table of the House.

Pension to Non-Government employees

547. SHRI P. UPENDRA : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether Government are considering a proposal for introduction of a pension scheme for non-